सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 11 ● अंक: 67 ● पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, शुक्रवार, 11 अप्रैल, 2025
मूल्य ₹ 3/-

बेहतर होगा कि आप कोशिश करें और नाकामयाब हो जाएं और उससे कुछ सीखें बजाये इसके की आप कुछ करें ही नहीं।

-मार्क जुकरबर्ग

धोनी आज लेंगे केकेआर की... 7 | कांग्रेस अधिवेशन ने बढ़ाई भाजपा... 3 | 'जनता भगवान भरोसे, भाजपा... 2

शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने लगाया आरोप

बिहार चुनाव के दौरान तहव्वुर को फांसी पर लटका देगी मोदी सरकार!

26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता तक पहुंचा भारत

- फांसी पर लटक कर बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक का काम करेगा राणा!
- बिहार चुनाव में तहव्वुर का इस्तेमाल करेगी बीजेपी
- पाकिस्तानी जेल में बंद कुलभूषण जाधव को भारत वापस लाने की मांग उठी

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। 26/11 हमले का मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत पहुंच चुका है। उसे तिहाड़ जेल में किसी गुप्त ठिकाने पर रखा गया है। अमेरिका से भारत पहुंचे तहव्वुर पर पटियाला कोर्ट में देर रात तक चली बहस में जज चन्द्रजीत सिंह ने उसे 18 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा दिया है।

एनआईए की पूछताछ सें सबंधित एक डायरी बनेगी जो सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश कि जाएगी। तहव्वुर के भारत पहुंचते ही एक और कहानी तैयार हो रही है और वह है राजनीतिक गुणा-भाग की स्क्रिप्ट वाली कहानी। विपक्ष ने सरकार पर तहव्वुर को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। शिवसेना यूबीटी खुलकर इस मुद्दे पर सामने आई है और फायर ब्रांड नेता संजय राउत ने कहा है कि तहव्वुर को फांसी पर लटकाकर सरकार इसका फायदा बिहार चुनाव में उठाना चाहती है। संजय राउत ने तहव्वुर को बीजेपी का स्टार प्रचारक बताया है। वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर किसी भी राजनीतक दल को राजनीति नहीं करने की चेतावनी दी है।

इंतजार क्यों, तुरंत हो फांसी : राउत

शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने 26/11 अटैक के मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार राणा को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान फांसी पर लटका देगी। संजय राउत ने कहा कि राणा को तुरंत फांसी दी जानी चाहिए लेकिन सरकार उसे बिहार चुनाव के दौरान फांसी पर लटकाएगी। उन्होंने कहा कि राणा को भारत लाने के लिए 16 साल लंबी लड़ाई चली और यह कांग्रेस के शासन के दौरान शुरू हुई। इसलिए राणा को वापस लाने का श्रेय किसी को नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि राणा भारत प्रत्यर्पित होने वाला पहला आरोपी नहीं है। अतीत में 1993 के सीरियल ब्लास्ट के आरोपी अबू सलेम को भी भारत प्रत्यर्पित किया गया था। राउत ने कहा कि तहव्वुर का इस्तेमाल बीजेपी अपने स्टार प्रचारक के तौर पर कर रही है।

18

दिन की एनआईए कस्टडी में अमेरिका से भारत पहुंचे तहव्वुर को भेजा गया।

यह प्रत्यर्पण कोई प्रचार की जीत नहीं : चिदंबरम

अपने बयान में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि तथ्यों को स्पष्ट रूप से जान लीजिए। मोदी सरकार ने इस प्रक्रिया की न तो शुरुआत की, न ही कोई नई सफलता हासिल की। वह केवल उस संस्थागत ढांचे का लाभ उठा रही है, जिसे यूपीए सरकार ने वर्षों की मेहनत, समझदारी और राजनयिक दूरदर्शिता से खड़ा किया था। यह प्रत्यर्पण कोई प्रचार की जीत नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि जब भारतीय राज्य ईमानदारी, गंभीरता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ काम करता है, तब वह दुनिया के सबसे जटिल अपराधियों को भी कानून के कठघरे में खड़ा कर सकता है।

प्रत्यर्पण: संयोग या प्रयोग

तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण ऐसे समय पर हुआ है जब बिहार में चुनावों की सरगर्मी अपने चरम पर है। बीजेपी हर मोर्चे पर विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी बिहार की जनता के बीच राष्ट्रवाद की भावना को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। यह मुद्दा चुनावी रणनीति में एक मास्टरस्ट्रोक बन सकता है। एक ऐसा कदम जो न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को केंद्र में लाए बल्कि विपक्ष को भी चुप कर दे। राजनीति में समय का बड़ा महत्व होता है। जब जनता महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी, और भ्रष्टाचार जैसे सवाल पूछ रही हो तब किसी राष्ट्र विरोधी के विरुद्ध फांसी जैसी कार्यवाही एक प्रभावशाली मोड़ ला सकती है।

मोदी ने कर दिखाया

भाजपा विधायक राम कदम ने तहव्वुर राणा को भारत लाने का श्रेय मोदी सरकार को दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो तहव्वुर राणा को भारत वापस नहीं ला पाई लेकिन इस काम को पीएम मोदी ने कर दिखाया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह विषय आरोप-प्रत्यारोप का हो सकता है। क्या इस पर राजनीति करनी चाहिए? कांग्रेस और अन्य दल अभी भी आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं। विपक्ष को उनके बारे में सोचना चाहिए जिनके परिवार के सदस्यों ने मुंबई आतंकी हमले के दौरान अपनी जान गंवाई। मोदी सरकार ने उन परिवारों को न्याय देने का काम किया है।

हल्के में न लें राउत का बयान

संजय राउत के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। महाराष्ट्र और बिहार दोनों में राष्ट्रवाद एक संवेदनशील मुद्दा है। राउत का दावा बीजेपी उसे फांसी पर लटका देगी एक प्रतीकात्मक चेतावनी प्रातीत होती है कि इस मुद्दे को बीजेपी चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी।

बालाकोट स्ट्राइक से बन गया था समा

बिहार में जातीय समीकरणों के बीच अगर कोई एक भावना वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है तो वह है राष्ट्रवाद और यह बीजेपी को यह अच्छी तरह पता है। 2019 के चुनाव में बालाकोट स्ट्राइक ने बीजेपी को बड़ी बढ़त दिलाई थी। अब 2025 में तहव्वुर राणा का कार्ड वही प्रभाव दोहराने की कोशिश करेगा। बीजेपी का यह दांव विपक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है । विपक्ष अगर इसका विरोध करता हैं तो उस पर राष्ट्रविरोधी होने का आरोप लगेगा। अगर विपक्ष चुप रहता है तो बीजेपी को खुला मैदान मिल जाएगा।

'जनता भगवान भरोसे, भाजपा नफरत फैलाने में व्यस्त'

सपा मुखिया अखिलेश यादव बोले- यूपी की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ध्वस्त

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है, उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में गरीब मरीजों को इलाज और दवाएं नहीं मिल रही हैं, सरकारी अस्पतालों में स्टाफ और जांच सुविधाओं का अभाव है, जबकि बीजेपी सरकार जनता की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय समाज में नफरत फैलाने की राजनीति कर रही है।

सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में मेडिकल कॉलेज के नाम पर सिर्फ बिल्डिंगे दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार के सारे दावे फेल है,पूरी व्यवस्था भगवान भरोसे है, समाजवादी सरकार में लखनऊ में विश्वस्तरीय कैंसर संस्थान समेत कई जिलों में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाए गए लेकिन यह सरकार मेडिकल संस्थानों को पर्याप्त बजट नहीं दे रही है। बिल्डिंगें खड़ी हैं लेकिन उनमें इलाज और पढ़ाई दोनों नहीं हो पा रही है। डॉक्टर, नर्स और तकनीकी स्टाफ की भारी कमी है. मरीजों को समय से इलाज नहीं मिल पाता, जिसके चलते वे मजबूरी में निजी अस्पतालों का रुख करते हैं और वहां उन्हें इलाज के नाम पर मोटी रकम चुकानी पड़ती है।

झांसी के किसानों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को ज्ञापन देकर बुन्देलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के लिए चिह्नित 36 गांवो को सर्किल रेट से बाहर किए जाने की शिकायत की और सर्किल रेट बढ़ाने की मांग की।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के नाम पर सिर्फ दिखावा

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय लखनऊ में विश्वस्तरीय कैंसर संस्थान, सैफई, आज़मगढ़, बांदा, कन्नौज, गाजीपुर जैसे कई जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए गए थे, लेकिन बीजेपी सरकार उन्हें पर्याप्त बजट तक नहीं दे रही है।

जनता के सामने खुलने लगी है बीजेपी सरकार की नाकामी

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार की नाकामी अब जनता के सामने है, इसलिए वह शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान हटाकर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि जनता अब सब समझ चुकी है और आने वाले चुनावों में इसका जवाब देगा।

स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार

पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। दवाएं समय पर नहीं मिलतीं, मशीनें या तो खराब रहती हैं या उनकी सुविधा ही नहीं होती। मरीजों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। कई बार गंभीर मरीज समय पर इलाज न मिलने से दम तोड़ देते हैं।

मध्य प्रदेश सरकार जनता के जीवन से कर रही खिलवाड़: मुकेश नायक

» प्रदेश की तीन घटनाओं पर कांग्रेस हमलावर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि ग्वालियर में की गई अवैध प्रतिनियुक्ति, रीवा में ब्लैकलिस्ट कंपनी द्वारा सप्लाई किए गए इंजेक्शन से मरीजों की हालत बिगड़ना, और दमोह में फर्जी डॉक्टर द्वारा की गई सर्जरी से 7 लोगों की मौत- ये तीनों घटनाएं मध्यप्रदेश सरकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार और गैरजिम्मेदाराना कार्यशैली का स्पष्ट प्रमाण हैं।

मुकेश नायक ने कहा कि ये घटनाएं अलग-अलग नहीं, बल्कि एक असंवेदनशील, गैर-जवाबदेह और भ्रष्ट शासन तंत्र की उपज हैं। यदि सरकार इन पर त्वरित, निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई नहीं करती, तो कांग्रेस पार्टी इन्हें सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाएगी। यह अब किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि प्रदेश के नागरिकों के जीवन और अधिकारों की लड़ाई है। नायक ने कहा कि ग्वालियर में पशु चिकित्सक डॉ. अनुज शर्मा को हेल्थ ऑफिसर बनाना योग्यता और नियमों के खिलाफ था। अब यह सामने आ चुका है कि 22 नवंबर 2022 को तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने सबसे पहले सिफारिशी नोटशीट लिखी थी। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जब शासन से जवाब मांगा गया, तब यह तथ्य सामने आया। शासन ने शुरू में अदालत से यह सिफारिशी नोटशीट छिपाने की कोशिश की और सीलबंद लिफाफे में जब उसे पेश किया गया, तो न्यायालय ने इसे जानबूझकर तथ्य छिपाने का प्रयास माना।

हाईकोर्ट की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। उन्होंने कहा कि यह केवल एक अवैध नियुक्ति नहीं, बल्कि न्यायपालिका को गुमराह करने, व्यवस्था को तोड़ने और सिफारिशी राजनीति को संस्थागत रूप देने का प्रयास है।

रीवा मेडिकल कॉलेज की लापरवाही

मुकेश नायक ने कहा कि रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में गुजरात की ब्लैकलिस्टेड कंपनी रेडियंट पार्टरल्स लिमिटेड से सप्लाई हुए इंजेक्शन लगाने के बाद 5 महिलाओं की यादाश्त चली गई। नायक ने कहा कि यह शर्मनाक है कि स्वास्थ्य विभाग ने एक प्रतिबंधित कंपनी से दवा मंगवाई। यह वही विभाग है जो उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के अधीन है और यह घटना उनकी प्रशासनिक नाकामी का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

फर्जी डॉक्टर करता रहा हार्ट सर्जरी

नायक ने कहा कि दमोह जिले के निजी अस्पताल में फर्जी चिकित्सक नरेंद्र यादव उर्फ एनकेएम जॉन द्वारा की गई हार्ट सर्जरी से 7 मरीजों की मौत हो गई। यह घटनाएं जनवरी से फरवरी के बीच की हैं। अब मामला सामने आने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तीन दिन की जांच का आदेश दिया है। नायक ने कहा कि जब एक फर्जी डॉक्टर बिना वैध प्रमाणपत्रों के हार्ट सर्जरी करता है और सरकार की मशीनरी उसे रोक नहीं पाती, तो यह लापरवाही नहीं, जनजीवन से किया गया क्रूर मजाक है।

महाबोधि मंदिर प्रबंधन कानून में हो संशोधन: मायावती

बोलीं बसपा प्रमुख- भारत और भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार

» केंद्र सरकार और बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बोधगया महाबोधि मंदिर प्रबंधन कानून 1949 और हाल ही में संसद से पारित हुए वक्फ कानून में किए गए बदलावों पर कड़ी आपत्ति जताई और दोनों मामलों में सरकार से तत्काल संशोधन की मांग की।

मायावती ने कहा कि बोधगया का महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, लेकिन वहां की देखरेख और पूजा-पाठ में गैर-बौद्धों की भागीदारी बौद्ध समुदाय की आस्था के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि 1949 के कानून में मंदिर प्रबंधन समिति में चार हिन्दू और चार बौद्ध प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था, जिसकी वजह से विवाद बढ़ा है. मायावती ने इस कानून को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ बताया और मांग की कि मंदिर की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों को दी जाए। वहीं अंत में मायावती ने देश और देशवासियों की सुरक्षा पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आतंकी गतिविधियों के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारों को राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाने चाहिए। ताकि भारत और भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बीएसपी प्रमुख ने केंद्र सरकार से सभी विवादित मामलों में ईमानदारी और संवेदनशीलता से काम लेने की अपील की है।

बाबा साहेब के दिये अधिकारों से अब भी वंचित हैं गरीब वर्ग

मायावती ने 14 अप्रैल को आने वाली बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने दलितों और वंचितों को सम्मान की जिंदगी दिलाने के लिए अपने जीवन का हर पल समर्पित किया। लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी उनके द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकारों का पूरा लाभ इन वर्गों को नहीं मिल रहा। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, जिसे अब कुछ लोग सनातनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चलकर ही 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी की स्थापना की गई थी और पार्टी आज भी उनके अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है।

केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम को निलंबित करे

बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने वक्फ कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम को शामिल करने का प्रावधान गलत प्रतीत होता है, तथा मुस्लिम समुदाय भी इस पर आपत्ति जता रहा है। बसपा प्रमुख ने आगे कहा कि बेहतर होगा कि केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम पर पुनर्विचार करे तथा उसे निलंबित कर दे ताकि अन्य समान विवादास्पद प्रावधानों में सुधार हो सके। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि भारत में भारतीयों की सुरक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों को अपने राजनीतिक हितों को छोड़कर भारतीय कानून के तहत आतंकवादियों के खिलाफ निष्पक्ष और ईमानदार सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इससे पहले मायावती ने एक्स पोस्ट में कहा था कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता व विपक्ष को सुनने के बाद, निष्कर्ष यही निकलता है कि केन्द्र सरकार यदि जनता को इस बिल को समझने के लिए कुछ और समय दे देती तथा उनके सभी सन्देहों को भी दूर करके जब इस बिल को लाती तो यह बेहतर होता। उन्होंने आगे लिखा था कि लेकिन दुःख की बात यह है कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लाकर जो इसे पास कराया है यह उचित नहीं और अब इस बिल के पास हो जाने पर यदि सरकारें इसका दुरुपयोग करती हैं तो फिर पार्टी मुस्लिम समाज का पूरा साथ देगी अर्थात् ऐसे में इस बिल से पार्टी सहमत नहीं है। वहीं, मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उस पर दलितों और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण लागू करने के मुद्दे पर छलावापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया।

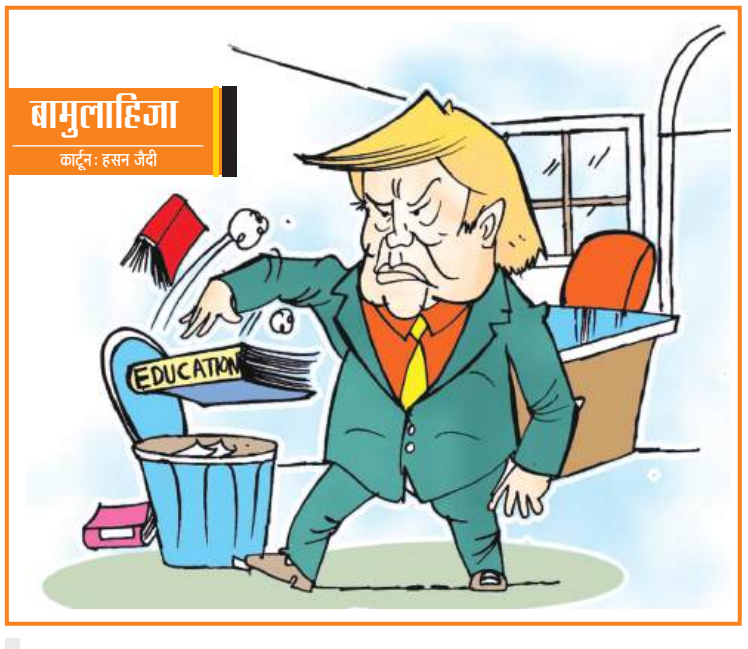

बैंकों में मराठी का इस्तेमाल नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन: राज ठाकरे

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शीर्ष बैंक निकाय भारतीय बैंक संघ से कहा है कि वह बैंकों को निर्देश दे कि वे अपनी सेवाओं में आरबीआई के मानदंडों के अनुसार मराठी का उपयोग करें, अन्यथा उनकी पार्टी अपना आंदोलन तेज करेगी। मनसे नेताओं द्वारा बुधवार को भारतीय बैंक संघ को सौंपे गए पत्र में ठाकरे ने यह भी कहा कि यदि बैंक अपनी सेवाओं में तीन-भाषा फार्मूले अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा (महाराष्ट्र के मामले में मराठी) का पालन नहीं करते हैं, तो कानून और व्यवस्था के लिए बैंक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

ठाकरे ने आईबीए को लिखे पत्र में कहा, आप बैंकों को मराठी भाषा का उपयोग करने के लिए आवश्यक निर्देश दें, अन्यथा मनसे अपना आंदोलन तेज कर देगी और उसके बाद कानून एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित बैंकों की होगी। पत्र में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र और निजी बैंकों में क्षेत्रीय भाषाओं के इस्तेमाल को लेकर एक परिपत्र जारी किया है। इसके अनुसार, बैंकों में बोर्ड तीन भाषाओं में होने चाहिए। हिंदी, अंग्रेजी और उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा। पत्र में कहा गया है कि यहां तक कि सेवाएं भी तीन भाषाओं में होनी चाहिए।

कांग्रेस अधिवेशन ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन!

- गुजरात में भरी मोदी-शाह के खिलाफ हुंकार
- राहुल-खरगे ने जमकर किया एनडीए सरकार पर प्रहार
- 2027 में सरकार बनाने की कवायद पर जोर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

अहमदाबाद। कांग्रेस ने मोदी व शाह को चित करने के इरादे से अपना अधिवेशन इसबार गुजरात में कांग्रेस ने 64 साल बाद अपना अधिवेशन आयोजित किया है। उधर जिस तरह से अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष ने हुंकार भरा उससे भाजपा सहम गई। कांग्रेस ने यह बैठक ऐसे वक्त पर किया है जब वह सिर्फ राज्यों में सरकार चला रही है। गुजरात बीजेपी को गढ़ है इसके बाद भी राहुल गांधी ने यह कदम उठाया है।

लोकसभा चुनावों में 99 सीटों जीतकर अपने को थोड़ा मजबूत करने वाली कांग्रेस देश के कई राज्यों में दशकों से सत्ता से बाहर है। उधर कांग्रेस के इस बैठक व राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे समेत बड़े नेताओं के बयान पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। चूकि इस बैठक में सरदार पटेल के बहाने कांग्रेस ने ओबीसी का मुद्दा उठाकर एनडीए की मोदी सरकार को घेरा। वहीं भाजपा ने कांग्रेस से पूछ लिया उसके शीर्ष नेतृत्व में कितने ओबीसी हैं।

मौन से बाहर निकलने की रणनीति

कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन को 2027 चुनावों की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने लोकसभा में नेता विपक्ष बनने के बाद तीसरी दो बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। पहली बार 2024 में आए थे। इसके बाद वह पिछले महीने मार्च में आए थे। उन्होंने तब तमाम नेताओं के साथ निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की की थी। विश्वस्त सूत्रों की मानें तो कांग्रेस अब महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि पर खुद को मजबूत करना चाहती है। बीजेपी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से कांग्रेस नेताओं की दूरी को लेकर अभी तक निशाना साधती आई है। अधिवेशन के पहले दिन जब अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल मेमोरियल स्मारक में राहुल गांधी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि कांग्रेस नेता ने सरदार पटेल का अपमान किया।

कांग्रेस अध्यक्ष का पार्टी नेताओं को सख्त संदेश

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पार्टी नेताओं को सख्त संदेश देते कहा कि जो लोग पार्टी के काम में हाथ नहीं बटाते उन्हें आराम करने की आवश्यकता है और जो जिम्मेदारी नहीं निभाते, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। उन्होंने यहां कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति निष्पक्ष तरीके से होगी और चुनावों में उम्मीदवारों के चयन में उन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। खरगे ने कहा, संगठन निर्माण में जिला अध्यक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इनकी नियुक्ति कांग्रेस के दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पक्षता से होनी है। उनके अनुसार, जिला अध्यक्ष को अपनी नियुक्ति के एक साल के अंदर बूथ कमेटी, मंडल कमेटी, ब्लॉक कमेटी और जिला कमेटी बेहतरीन लोगों को जोड़ते हुए बनाना है तथा इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हमने भी देश भर से जिला अध्यक्षों की तीन बैठकें बुलाईं। राहुल जी और हमने उनसे बात की। उनसे जानकारी ली। हम भविष्य में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में जिला अध्यक्षों को शामिल करने वाले हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग पार्टी के काम में हाथ नहीं बटाते, उन्हें आराम करने की आवश्यकता है। जो जिम्मेदारी नहीं निभाते, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए।

आप के आने से बना त्रिकोण

हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के बाद झारखंड (गठबंधन सरकार) को छोड़कर कांग्रेस सभी जगह पर सत्ता से बाहर हैं। ऐसे में जब कांग्रेस को राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में चल रहा है तब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस खुद को मजबूत कर पाएगी? खासकर बीजेपी की प्रयोगशाला और पीएम मोदी-गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य में है? इस सीधा जवाब है कि कांग्रेस के लिए सत्ता का सपना तो काफी मुश्किल है, अगर वह 2027 में चुनावों में 2017 का प्रदर्शन दोहरा ले तो भी बड़ी बात है। इसकी वजह है राज्य में आम आदमी पार्टी (आप) के आने से बना त्रिकोण। आप ने 2022 के विधानसभा चुनावों में 14 फीसदी वोट झटका सिर्फ पांच सीटें जीती थीं लेकिन कांग्रेस की कमर तोड़ दी थी।

सभी वरिष्ठ नेताओं ने अधिवेशन में रखी अपनी बात

कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के पहले दिन पार्टी के तमाम दिग्गज नेता सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल हुए। इसमें सरदार पटेल और पहले प्रधानमंत्री नेहरू के बीच के संबंधों को लेकर किए गए दुष्प्रचार पर नेताओं ने राय रखी, हालांकि अधिवेशन में प्रियंका गांधी की गैरहाजिरी चर्चा का विषय बनी तो दो महासचिवों को सवालों का सामना करना पड़ा। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन के पहले दिन विस्तारित सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक शहर के सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक पर हुई। इसमें में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत 158 सदस्यों ने हिस्सा लिया। हालांकि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अनुपस्थित रहीं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रियंका गांधी की अनुपस्थिति मीडिया के बीच चर्चा का विषय रही,

हालांकि बाद में इस मुद्दे पर जब पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश से सवाल हुआ तो उन्होंने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि बैठक में 35 सदस्य अनुपस्थित थे और किसी एक व्यक्ति को अलग करना उचित नहीं है। इसी सवाल का जवाब देते हुए पार्टी महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने कहा कि प्रियंका गांधी ने पार्टी से पहले ही अनुरोध किया था कि उन्हें विदेश में पूर्व-व्यस्तताओं में शामिल होने के लिए एआईसीसी सत्र और संसद सत्र को छोड़ने की अनुमति दी जाए और पार्टी ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है।

राहुल गांधी की सोच स्पष्ट नहीं देश ने उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर दिया : रविशंकर प्रसाद

वक्फ एक्ट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में एक बार कहा था कि 6-7 साल में एक व्यक्ति युवा हो जाता है। फिर उन्होंने कहा कि तपस्या से गर्मी आ जाती है। आज वैसा ही नया सिद्धांत कुछ दिखाई पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी को वक्फ पर बोलने की कोशिश करने के लिए अहमदाबाद का इंतजार करना पड़ा। मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी 12-13 घंटे सदन में बहस हुई आप खुद बैठे थे, वक्फ पर आपने क्यों नहीं बोला। ये दिखाता है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इसके बारे में उनकी (राहुल गांधी) सोच में स्पष्टता नहीं होती है। अपना हमला जारी रखते हुए रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि इससे पता चलता है कि राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा है कि वक्फ के बारे में क्या बोलना है। मैं पूरे अधिकार से कह रहा हूं कि राहुल गांधी के पास इस बात की स्पष्टता नहीं है कि उन्हें किस मुद्दे पर और कब क्या रुख अपनाना चाहिए। उन्हें इन तीन सवालों का जवाब देना चाहिए। क्या आपको यह सही लगता है या गलत कि वक्फ की 8 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली संपत्ति पर गरीब मुसलमानों और बेटियों के लिए कोई अस्पताल, स्कूल, अनाथालय या कौशल केंद्र नहीं बनाया गया है? क्या आपको इस बात से परेशानी है कि मुस्लिम समुदाय की विधवाओं की तरक्की के लिए वक्फ में सुधार किया जा रहा है? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आजकल किसी ने उन्हें ओबीसी पर बोलने के लिए चिट थमा दी है। तो, क्या आपको कोई दिक्कत है अगर वक्फ में संशोधन के जरिए पिछड़े मुसलमानों पर विचार किया जा रहा है? वक्फ पर उनका रुख देरी से आया है। उनसे कहा गया कि उन्होंने वक्फ के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए उन्होंने सिर्फ कहने के लिए बिल को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि इस देश ने राहुल गांधी को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। राहुल गांधी जब ओबीसी की बात करते हैं तो सबसे पहले ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी के सबसे उच्च निर्णय लेना में ओबीसी को जगह है क्या? यही कांग्रेस पार्टी की सच्चाई है।

जिद... सच की

Sanjay Sharma
editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

टैरिफ मामले में भारत को रखनी होगी अपनी बात

> फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमरीका यात्रा के दौरान दोनों देशों ने संयुक्त रूप से इन वार्ताओं पर सहमति जताई थी। ऐसे में सवाल यह है कि भारत को इन वार्ताओं में पारस्परिक टैरिफ के संदर्भ में किस प्रकार का रुख अपनाना चाहिए? पिछले दो महीनों में अमरीका को दी गई कई रियायतों से स्पष्ट है कि ऐसी एकतरफा छूट अमरीका की मांगों को बढ़ाने की भूख को और बढ़ाएगी।

भारी दबाव को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत जैसे देशों के ऊपर टैरिफ लगाने के निर्णय को तीने महीने के लिए टाल दिया है। इस बीच चीन पर टैरिफ की मात्रा 124 प्रतिशत बढ़ा दी गई है। अब जबकि राष्ट्रपति द्वारा मामले को तीन महीने टालने की बात की गई है ऐसे में भारत को अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए ताकि से टैरिफ कुछ राहत मिल सके। अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अपनी पारस्परिक टैरिफ (आयात शुल्क) योजना की घोषणा कर दी इससे पारस्परिक टैरिफ अंतरराष्ट्रीय व्यापार में काफी अनिश्चितता और उथल-पुथल पैदा हो गई है। भारत के लिए 27 प्रतिशत टैरिफ का यह बोझ ऐसे समय पर आया है, जब वह अमरीका के साथ एक बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर गहन वार्ता कर रहा है। यह उल्लेखनीय है कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमरीका यात्रा के दौरान दोनों देशों ने संयुक्त रूप से इन वार्ताओं पर सहमति जताई थी। ऐसे में सवाल यह है कि भारत को इन वार्ताओं में पारस्परिक टैरिफ के संदर्भ में किस प्रकार का रुख अपनाना चाहिए? भारत को केवल अमरीका के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। पिछले दो महीनों में अमरीका को दी गई कई रियायतों से स्पष्ट है कि ऐसी एकतरफा छूट अमरीका की मांगों को बढ़ाने की भूख को और बढ़ाएगी। बीटीए वार्ता केवल पारस्परिक शुल्क हटाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। भारत को अमरीका को दी जाने वाली हर रियायत के बदले अतिरिक्तबाजार पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। कपड़ा, परिधान और चमड़ा उद्योग जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में शुल्क रियायतें हासिल करना भारत के लिए महत्त्वपूर्ण होगा। भारत की रियायतें इस शर्त पर होनी चाहिए कि अमरीका भविष्य में पारस्परिक शुल्क जैसे उपाय नहीं करने का वचन दे। बीटीए में ऐसा प्रावधान शामिल होना चाहिए कि यदि अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं करता, तो भारत भी अमरीका के प्रति अपनी किसी भी प्रतिबद्धता को निभाने के लिए बाध्य नहीं होगा। भारत को बीटीए का दायरा यथासंभव सीमित रखना चाहिए। इसे केवल वस्तु व्यापार तक ही सीमित रखा जाए अन्यथा, बौद्धिक संपदा अधिकार, सरकारी खरीद, डिजिटल जैसे मुद्दों वाले कई जटिल क्षेत्रों में अमरीका को रियायतें देनी पड़ सकती हैं। विशेष रूप से, पेटेंट के क्षेत्र में अमरीका की लंबित मांगों पर सावधानी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इससे जेनेरिक दवाओं के बाजार में प्रवेश में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस क्षेत्र में अमरीका की मांगों को स्वीकार करने से दवाओं की कीमतें लगातार बढ़ सकती हैं, जिससे सस्ती स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता एक सपना बनकर रह जाएगी।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा खींच दिखाई राह

जयसिंह रावत

तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 अप्रैल, 2025 को दिया गया निर्णय भारतीय संघीय ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि राज्यपाल किसी विधेयक को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकते, उन्हें या तो मंजूरी देनी होगी, असहमति के साथ लौटाना होगा, या राष्ट्रपति के पास भेजना होगा। यह निर्णय केवल एक कानूनी निर्देश नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यपालों के लिए एक स्पष्ट 'लक्ष्मण रेखा' खींच देने जैसा है, जिससे बाहर जाना अब संविधान की आत्मा के विरुद्ध माना जाएगा। तमिलनाडु प्रकरण और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने केवल एक संवैधानिक संकट का समाधान नहीं किया, बल्कि एक बुनियादी सवाल भी खड़ा किया है। लोकतांत्रिक भारत में राज्यपाल की प्रासंगिकता।

राज्यपाल का पद अगर लोकतंत्र के सहायक संरक्षक की भूमिका निभाए, तो वह उपयोगी हो सकता है, लेकिन जब वह केंद्र सरकार का राजनीतिक उपकरण बन जाता है, तब यह पद संविधान की आत्मा के विरुद्ध चला जाता है। आज का युग जन-जागरूकता और जवाबदेही का है। अब समय आ गया है कि हम यह मूल्यांकन करें कि क्या वाकई राज्यपाल का पद भारतीय संघीय ढांचे को मजबूत कर रहा है?? तमिलनाडु में राज्यपाल रवि ने राज्य सरकार द्वारा पारित 12 विधेयकों को महीनों तक रोके रखा, जिनमें से कई को बिना कारण बताए राष्ट्रपति के पास भेज दिया और कुछ को लौटाया भी। उन्होंने सदन के अभिभाषण के दौरान सरकार द्वारा तैयार भाषण को अधूरा पढ़ा और बीच में ही वॉकआउट कर दिया। ये सभी घटनाएं संविधान की भावना और राज्यों की स्वायत्तता के खिलाफ मानी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने इन कृत्यों को 'लोकतंत्र की उपेक्षा' बताया और स्पष्ट किया कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना अनिवार्य है।

यह कोई पहली घटना नहीं है जब राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच टकराव सामने आया हो। उत्तराखंड में 2016 में बहुमत परीक्षण से पहले राष्ट्रपति शासन लागू कराना, महाराष्ट्र में 2019 में तड़के सरकार बनवाना, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में असंवैधानिक हस्तक्षेप, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में राज्यपालों द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह की उपेक्षा। ये सभी उदाहरण बताते हैं कि राज्यपाल का पद बार-बार विवादों में रहा है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे रोमेश भंडारी ने 1998 में कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की थी, जिसे बाद में न्यायपालिका ने असंवैधानिक करार दिया। इसी प्रकार, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे रामलाल, जो पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, ने 1984 में एन.टी. रामाराव की निर्वाचित सरकार को हटा दिया और केंद्र के समर्थन से विपक्षी नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। इस निर्णय के खिलाफ जनांदोलन खड़ा हुआ, जिसे अंततः राष्ट्रपति को पलटना पड़ा।

राज्यपाल के पद को लेकर संविधान सभा में भी गहन बहस हुई थी। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया था कि राज्यपाल केवल 'संवैधानिक प्रमुख' होंगे और वे अपनी व्यक्तिगत राय से नहीं, बल्कि राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। कुछ सदस्यों ने यह चिंता भी जताई थी कि राज्यपाल कहीं केंद्र सरकार का प्रतिनिधि बनकर राज्यों की स्वायत्तता को बाधित न करे। लेकिन यह माना गया कि अगर पद का उपयोग संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर हो, तो यह संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकता है। संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल को 'नामित प्रमुख' के रूप में देखा था एक ऐसा पद जो केवल सलाहकार भूमिका निभाएगा, और राज्य की चुनी हुई सरकार की सिफारिशों पर ही कार्य करेगा। परन्तु आज की स्थिति देखें, तो साफ प्रतीत होता है कि राज्यपाल कई बार संविधान निर्माताओं की उस भावना से विचलित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को बार-बार दखल देना पड़ रहा है, जो इस व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करता है।

निस्संदेह, यदि राज्यपाल की भूमिका बार-बार अलोकतांत्रिक साबित होती रहे, तो इसके विकल्पों या इस पद की समाप्ति पर गंभीर विचार जरूरी है ताकि सत्ता नहीं, संविधान सर्वोपरि हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन यह नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर होती है। इसी कारण राज्यपालों की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं।

राजनीतिक हित साधने का जरिया न बने भाषा

विश्वनाथ सचदेव

महाराष्ट्र सरकार के एक अधिकारी को मराठी न बोल पाने की सज़ा भुगतनी पड़ी। मातृभाषा मराठी के प्रति अतिरिक्त लगाव वाले कुछ मराठी युवाओं ने यह सज़ा दी थी। उन्हें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) का संरक्षण प्राप्त था। अब मनसे के नेता राज ठाकरे ने अपने अनुयायियों से कह दिया है कि महाराष्ट्र में मराठी बोलने की अनिवार्यता के लिए अभियान जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। लोग समझ गये हैं। लोग कितना समझे हैं, और राज्य में मराठी भाषा का उपयोग कितना बढ़ जायेगा, यह तो आने वाला कल ही बतायेगा, लेकिन यह बात तो सहज समझ में आने वाली है कि जो जहां रह रहा है, उसे क्षेत्र-विशेष की भाषा तो आनी ही चाहिए। लेकिन यहीं इस बात की समझ की भी अपेक्षा की जाती है कि हमारा संविधान रोजी-रोटी के लिए कहीं भी आने-जाने, बसने का अधिकार देश के हर नागरिक को देता है। आसेतु-हिमालय सारा भारत देश के सब नागरिकों का है, सबको कहीं भी जाकर बसने का अधिकार है। ऐसे में, क्षेत्र-विशेष की भाषा बोलने की शर्त हर नागरिक के लिए लागू करना शायद उतना व्यावहारिक नहीं होगा, जितना समझा जा रहा है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि कोई भाषा न बोल पाने वाला उस भाषा के प्रति अवमानना का भाव रखता है।

यहीं इस बात को रेखांकित किया जाना ज़रूरी है कि अपनी भाषा के प्रति लगाव का भाव होना एक स्वाभाविक स्थिति है, अपनी भाषा के प्रति प्यार और सम्मान का भाव होना ही चाहिए, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि हम देश की अन्य भाषाओं के प्रति अवमानना का भाव रखें। देश की सारी भाषाएं हमारी भाषाएं हैं, और हमें सब पर गर्व होना चाहिए।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विभिन्न भाषाओं से समृद्ध हमारे भारत में भाषा के नाम पर विवाद खड़े किये जाते हैं। इस मुद्दे पर कई बार विभिन्न राज्यों में हिंसक घटनाएं भी हो चुकी हैं। उस स्थिति का मुख्य कारण भाषा को राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का माध्यम बनाना है। यह एक हकीकत है कि भाषा की इस राजनीति ने देश के अलग-अलग हिस्सों में अप्रिय स्थितियां पैदा की हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक आदि राज्यों में हमने इस राजनीति के दुष्परिणाम देखे हैं। अब भी समय-समय पर इन दुष्परिणामों की चिंगारियां भड़क उठती हैं।

बहरहाल, जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है भाषाई आंदोलन यहां के राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। मराठी संस्कृति और भाषा की रक्षा के नाम पर, मराठी अस्मिता की दुहाई देकर राजनीतिक दलों का गठन तक हुआ है। मराठी मानुष के हितों का नाम लेकर राज्य में समय-समय पर आंदोलन होते रहे हैं। इस संदर्भ में 'मनसे' की हाल की कार्रवाई ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाली है।

हमारे देश में राज्यों का गठन भाषाई आधार पर हुआ है। ये भाषाएं हमारी कमज़ोरी नहीं, ताकत हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमारी हर भाषा निरंतर समृद्धि की दिशा में बढ़े, बढ़ती रहे। भाषा के विकास का मतलब यही नहीं है कि उसका विस्तार कितना हो गया है अथवा उस भाषा के बोलने वालों की संख्या कितनी बढ़ गयी है। भाषा के विकास का अर्थ यह भी है कि भाषा की क्षमता कितनी बढ़ी है अर्थात नये-नये विषयों को समझने-समझाने में भाषा कितनी सक्षम हो गयी है या होती जा रही है। साहित्य, संस्कृति, कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई भाषा कितनी समृद्ध है, यही तथ्य उसके विकास का असली पैमाना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि आज भाषा के नाम पर जो आंदोलन-अभियान चलाये जा रहे हैं उनके पीछे असली मकसद भाषा की समृद्धि नहीं, राजनीतिक हितों को साधने की हवस है। यहां हितों के बजाय स्वार्थ कहना अधिक उपयुक्त होगा। किसी अफसर को राज्य-विशेष की भाषा बोलनी नहीं आती तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे सरेआम थप्पड़ मार दिया जाये। भाषा के हित साधने का यह तरीका अनुचित ही नहीं, आपराधिक भी है। उचित तरीका तो यह है कि हम अपनी भाषा को इतना समृद्ध बनायें कि हर किसी को उसे सीखने, काम में लेने की इच्छा होने लगे।

लेकिन हमारे यहां स्थित उल्टी है। तमिलनाडु वाले कहते हैं कि हम पर हिंदी थोपी जा रही है, कर्नाटक वालों को सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी में जानकारी दिये जाने पर ऐतराज है। महाराष्ट्र वालों को शिकायत है कि उनकी भाषा को 'क्लासिकल दर्जा' दिये जाने के बावजूद वह सम्मान नहीं दिया जा रहा जिसकी वह अधिकारी है। और दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि इन सब के पीछे भाषा विशेष के प्रति प्यार या सम्मान का भाव नहीं होता, अक्सर राजनीतिक स्वार्थ ही इसका कारण बनते हैं। यदि बात सिर्फ प्यार या सम्मान की ही है तो राज ठाकरे की चिंता राज्य में मराठी माध्यम के स्कूलों की संख्या का घटना होती। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में दस साल पहले की तुलना में मराठी माध्यम के स्कूल आज कहीं कम हैं। वर्ष 2014-15 में मुंबई महानगर पालिका मराठी माध्यम के 368 स्कूल चलाती थी, आज ऐसे सिर्फ 262 स्कूल हैंङ्क अर्थात दस वर्षों में मराठी माध्यम की सौं शालाएं बंद हो गयी हैं! चिंता इस कमी पर होनी चाहिए। पर कोई नहीं पूछ रहा कि यह सौ स्कूल क्यों बंद हो गये। यह तो पूछा जा रहा है कि राज्य में फलां अफसर को मराठी बोलनी क्यों नहीं आती, यह कोई नहीं पूछ रहा कि मराठी माणुस अपने बच्चों को मराठी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाना क्यों पसंद नहीं कर रहा? अपनी भाषा के प्रति प्यार और सम्मान के भाव का यह भी एक मतलब है कि हम उसकी क्षमता में विश्वास रखें।

हनुमान जयंती

नासै रोग हरैं सब पीरा...

हर साल चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस दिन का भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन संकटमोचन हनुमान जी का अवतरण हुआ था, इसलिए देशभर में इस दिन उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से इस दिन बजरंगबली की पूजा-अर्चना करके उनके प्रिय चीजों का भोग लगाते हैं तो उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस साल हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ था। इसी वजह से हर मंगलवार हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। इसके अलावा शनिवार भी हनुमान जी को प्रिय है।

पूजा विधि

हनुमान जयंती के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। बजरंगबली के समक्ष व्रत का संकल्प लें। इस दिन पीला या फिर लाल रंग का वस्त्र धारण करना शुभ होता है। हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली को सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर चोला चढ़ाएं। चमेली के तेल का दीपक लगाकर, गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। हनुमान जी को एक साबुत पान का पत्ता चढ़ाएं। बजरंगबली का प्रिय भोग गुड़-चना पूजा में शामिल करें। बूंदी के लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। अब हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। इस दिन घर में रामायण पाठ करना श्रेष्ठ होता है। आरती के दिन बाद जरुरतमंदों को यथाशक्ति वस्त्र, अन्न, धन का दान दें।

जन्मकथा

शास्त्रों में वर्णन है कि श्रृंगी ऋषि की यज्ञ में पूर्णाहुति के बाद अग्निदेव के हाथों मिली खीर को राजा दशरथ ने तीनों रानियों में बांटा। इसी दौरान वहां पहुंची एक चील प्रसाद की खीर का एक कटोरा चोंच में भरकर उड़ गई। यह हिस्सा किष्किंधा पर्वत पर भगवान शिव की उपासना कर रही अंजनी माता की गोद में जाकर गिरा। माता अंजनी से इस प्रसाद को ग्रहण किया, मान्यता है इससे फलस्वरूप देवी अंजनी की कोख से हनुमान जी ने जन्म लिया। बजरंगबली को वायु पत्र भी कहा जाता है।

श्रीराम भक्त को प्रसन्न करने के लिए लगाएं ये भोग

इमरती या जलेबी

हनुमान जयंती पर आप पवनपुत्र को इमरती या जलेबी का भोग लगा सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि उन्हें यह दोनों ही चीजें बेहद प्रिय हैं। ये भोग स्वरूप उन्हें अर्पित करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।

पान का बीड़ा

हनुमान जयंती के दिन आप अंजनीपुत्र को पान का बीड़ा भी भोग स्वरूप चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से दुश्मन से छुटकारा मिलता है। इतना ही नहीं जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इसमें चूना, तंबाकू जैसी चीजें शामिल नहीं होनी चाहिए।

बेसन के लड्डू

रामजी के प्रिय भक्त हनुमान को आप उनके जन्मोत्सव पर बेसन के लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। ये उनका प्रिय भोग है। ऐसा बताया जाता है कि यह भोग लगाने से भक्तों की सभी जायज मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

बूंदी के लड्डू या बूंदी

हनुमानजी को बूंदी के लड्डू या बूंदी का भोग कभी भी लगाया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों चीजें चढ़ाने से हनुमानजी प्रसन्न होते हैं। साथ ही भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं।

हंसना मना है

डॉक्टर - आपका लड़का पागल कैसे हो गया? पिता- वो पहले जनरल बोगी में सफर करता था। डॉक्टर - तो इससे क्या? पिता- लोग बोलते थे थोड़ा खिसको, थोड़ा खिसको, तभी से खिसक गया।

लड़की बंटी से- क्या कर रहे हो? बंटी - मच्छर मार रहा हूं। लड़की - अब तक कितने मारे? बंटी- पांच मारे.. तीन फीमेल और दो मेल। लड़की - कैसे पता चला कि मेल कौन है और फीमेल कौन? बंटी - तीन आईने पर बैठे थे और दो बियर के पास।

टीचर स्टूडेंट से- रमेश, बताओ अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों डूब रहे हों, तो तुम पहले किसको बचाओगे? रमेश- डूब जाने दूंगा दोनों को... आखिर दोनों एक साथ कर क्या रहे थे।

लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से- आई लव यू डियर, लड़की - तुझे मेरी चप्पल का साइज तो पता है ना? लड़का - अरे...पहले से ही गिफ्ट मांगने शुरू कर दिए, मैं नहीं दे रहा कोई सैंडल-वैंडल।

गोलू: रात भर मुझे नींद नहीं आई। मोलू- क्यों? गोलू- रात भर मैंने सपने में देखा कि मैं जाग रहा हूं।

कहानी — पड़ोसन का बर्तन

एक बार की बात है एक गांव में दो औरतें रहती थीं दोनों एक दूसरे की पड़ोसन थीं। एक बार एक औरत ने अपनी पड़ोसन से एक बर्तन उधार मांगा और दूसरे दिन उसने एक अन्य छोटे से बर्तन के साथ वह बर्तन वापस कर दिया। पड़ोसन को यह देखकर आश्चर्य हुआ उसने अपनी पड़ोसन से पूछा कि वह छोटा बर्तन कहां से आया? औरत ने जवाब दिया- तुम्हारे बड़े बर्तन ने छोटे बर्तन को जन्म दिया है। यह सुनकर पड़ोसन का दिमाग घूम गया कि यह कैसे हो गया लेकिन उसने उसे कुछ नहीं कहा। क्योंकि वह एक और बर्तन पाकर बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद पड़ोसन बर्तन फिर उधर मांगने आई। मगर इस बार उसने बर्तन अपनी पड़ोसन को वापस नहीं किया। पहली पड़ोसन ने अपनी पड़ोसन के बर्तन वापस मांगने पर उसने कहा - बर्तन! तुम्हारा बर्तन मर गया है। पड़ोसन ने हंसकर उससे पूछा कि बर्तन कैसे मर सकता है? इस पर उस औरत ने बड़ी चतुराई से कहा- अगर तुम्हारा बर्तन, दूसरे बर्तन को जन्म दे सकता है तो, मर भी सकता है। यह सुनकर पड़ोसन दंग रह गई। मगर अब उस पड़ोसन के पास बर्तन को खो देने के अलावा कोई दूसरा चुनाव नहीं था।

कहानी से सीख-अनेकों बार हम छोटे से लाभ के लिए अपने आप को मुसीबतों में डाल लेते हैं। अत: हमें तात्कालिक लाभ नहीं देखते हुए किसी विषय पर विस्तार पूर्वक सोचना चाहिए, कि क्या गलत है और क्या सही।

7 अंतर खोजें

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष

पुराना रोग परेशानी का कारण बन सकता है। अज्ञात भय सताएगा। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है। कुसंगति से बचें।

वृषभ

शत्रु भय रहेगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। शारीरिक कष्ट संभव है। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। भूमि व भवन संबंधी खरीद-फरोख्त की योजना बनेगी।

मिथुन

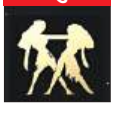

किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। यात्रा मनोरंजक रहेगी। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। कारोबार में बुद्धिबल से उन्नति होगी।

कर्क

लेन-देन में जल्दबाजी न करें। पुराना रोग उभर सकता है। दु:खद समाचार की प्राप्ति संभव है। किसी के उकसाने में न आएं। बात बिगड़ सकती है। थकान हो सकती है।

सिंह

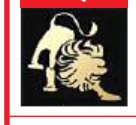

पराक्रम व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर-बाहर पूछ-परख रहेगी। आय में वृद्धि होगी। कारोबार का विस्तार होगा। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। प्रयास सफल रहेंगे।

कन्या

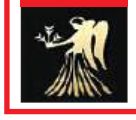

आय में वृद्धि होगी। कारोबार लाभप्रद रहेगा। दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं। दूर से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। घर में अतिथियों का आगमन होगा। व्यय बढ़ेगा।

तुला

प्रेम-प्रसंग में आशातीत सफलता प्राप्त होगी। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। सट्टे व लॉटरी से दूर रहें। भाग्य का साथ मिलेगा।

वृश्चिक

राजभय रहेगा। विवाद को बढ़ावा न दें। लेन-देन में जल्दबाजी हानि देगी। शारीरिक कष्ट संभव है। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। व्यवस्था में मुश्किल होगी।

धनु

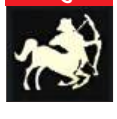

व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। नेत्र पीड़ा हो सकती है। मानसिक बेचैनी रहेगी। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे।

मकर

राज्य से प्रसन्नता रहेगी। कोई बड़ा काम हो सकता है। नई योजना बनेगी। नया उपक्रम प्रारंभ हो सकता है। सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा।

कुम्भ

आंखों को चोट व रोग से बचाएं। धन प्राप्ति सुगम होगी। सुख के साधन जुटेंगे। कारोबार लाभदायक रहेगा। नौकरी में उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। पूजा-पाठ में मन लगेगा।

मीन

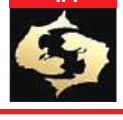

पुराना रोग उभर सकता है। अनहोनी की आशंका रहेगी। मातहतों से कहासुनी हो सकती है। पार्टनरों से मतभेद संभव है। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें।

बॉलीवुड | अॅपकमिंग

आठ साल बाद मनोज के साथ फिल्म बनाएंगे राम गोपाल

मनोज बाजपेयी बॉलीवुड के सबसे अलग अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं। वह जल्द ही एक हॉरर कॉमेडी फिल्म में नजर आने वाले हैं। इसका निर्देशन राम गोपाल वर्मा करेंगे। निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर अपने नए प्रोजेक्ट का एलान किया है। उन्होंने इस फिल्म की कहानी के बारे में बताया है। इस फिल्म में वह मनोज बाजपेयी के साथ काम करेंगे। मनोज बाजपेयी पहले राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या, शूल और कौन में काम कर चुके हैं। राम गोपाल वर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि वह और मनोज बाजपेयी एक बार फिर साथ आ रहे हैं। वह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म में साथ में काम करेंगे। निर्देशक ने बताया है कि उनकी फिल्म का टाइटल पुलिस स्टेशन में भूत है। फिल्म की टैगलाइन होगी आप मरे हुए को नहीं मार सकते। राम गोपाल वर्मा ने लिखा हॉरर, गैंगस्टर, रोमांटिक, पॉलिटिकल ड्रामा, एडवेंचर, थ्रिलर्स सब फिल्मों पर काम किया है, लेकिन हॉरर कॉमेडी पर कभी काम नहीं किया है। राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर फिल्म की स्टोरी के बारे में बताया है- जब हम डरे हुए होते हैं तो पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन जब पुलिस डरी हुई होगी तो वह किसके पास जाएगी? एक हादसे के बाद, एक पुलिस स्टेशन एक भूतिया स्टेशन बन जाता है। इससे सभी पुलिसकर्मी भूतों से बचने के लिए भागते हैं। आपको बता दें कि मनोज बाजपेयी ने राम गोपाल वर्मा के साथ कई फिल्मों में काम किया है। वह एक दूसरे के साथ आठ साल बाद काम करेंगे। दोनों ने साल 2017 में सरकार 3 में काम किया था। राम गोपाल वर्मा की वजह से ही मनोज बाजपेयी के करियर में उछाल आया। साल 1998 में आई उनकी फिल्म सत्या को लोगों ने खूब पसंद किया था।

मेरे लिए बंगलूरू और मुंबई दोनों शहर अजीज : दीपिका

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की परवरिश बंगलूरू में हुई। अभिनय की दुनिया में नाम कमाने वे मुंबई आईं। अक्सर उनसे पूछा जाता है कि मुंबई और बंगलूरू में से कौन सा शहर दिल के करीब है? अभिनेत्री हाल ही में इस सवाल का जवाब देती दिखी हैं। दीपिका पादुकोण ने आज बुधवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इसके साथ कैप्शन लिखा है, एक सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है..., बेंगलुरु या मुंबई? वीडियो में दीपिका से पूछा जा रहा है, क्या आप मुंबई में घर को मिस करती हैं? इस पर दीपिका कहती हैं, मैं मिस करती हूं, लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि मैं मुंबई में हूं। कोई और नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक अलग तरह की इच्छाशक्ति चाहिए। दीपिका आगे कहती हैं, मैं जब भी बंगलूरू वापस आती हूं तो यहां एकदम घर वाला अहसास होता है। यहां मैंने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बिताया है। मैं यहां पली-बढ़ी। मेरे दोस्त यहां हैं। पढ़ाई यहां से हुई। मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, सबकुछ यहीं रहा। यहां के अनुभव अलग रहे हैं। लेकिन, मुंबई ऐसी जगह है, जहां प्रोफेशनली मेरी लाइफ शुरू हुई। और अब घर भी यहां है। दीपिका ने आगे कहा, मुंबई की एनर्जी बहुत अलग किस्म की है। ऐसे में एक को छोड़कर दूसरे शहर को चुन पाना बहुत ही मुश्किल है। मुझे लगता है कि दोनों शहरों ने मेरी जिंदगी के 39 वर्षों पर गहरा असर छोड़ा है। अभिनेत्री के पोस्ट पर यूजर्स के कमेंट आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, बंगलूरू ने आपको प्यारा सा परिवार दिया। लेकिन, मुंबई ने इसे विस्तार दिया। यहां आपको रणवीर मिले। बेबी दुआ आई।

बोलीं- बंगलूरू में बचपन बीता और मुंबई अब घर है

एक अभिनेता पूरी दुनिया के लिए काम करता है: सनी देओल

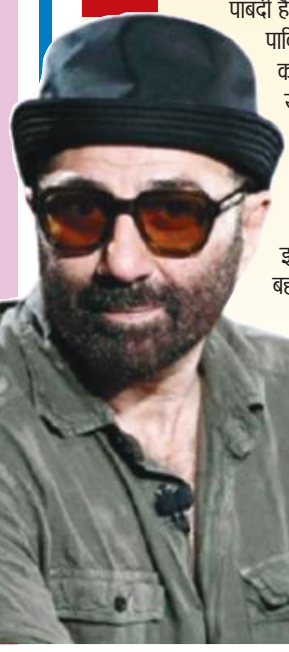

भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर कथित तौर पर पाबंदी है लेकिन पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान फिल्म अबीर गुलाल से बॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं। अब इस मामले पर बहस छिड़ गई है। सनी देओल जो अपनी फिल्म जाट को लेकर चर्चा में हैं, उनसे पूछा गया कि इस मामले पर उनकी क्या राय है? सनी देओल ने फवाद खान की वापसी पर बयान देते हुए कहा कि एकता और अवसर होने चाहिए। बॉर्डर और गदर के लिए मशहूर अभिनेता सनी देओल से एचटी सिटी ने पूछा कि क्या आप बॉलीवुड में फवाद खान का सपोर्ट करेंगे? इस पर सनी देओल ने जवाब दिया मैं राजनीति की तरफ नहीं जाउंगा क्योंकि वहां चीजें बहुत अस्त-व्यस्त हैं। हम अभिनेता हैं हम पूरी दुनिया में सभी के लिए काम करते हैं। चाहे कोई देखे या न देखे, हम सभी के लिए हैं। दुनिया जिस तरह की हो गई है, हमें पूरी दुनिया के लिए दरवाजे खोलने चाहिए और ज्यादा देशों को इसमें शामिल होने देना चाहिए। साल 2016 में पाकिस्तानी कलाकारों पर भारत में काम करने पर कथित तौर से पाबंदी लगा दी गई थी। हालांकि इस बारे में किसी की तरफ से कोई अधिकारिक बयान नहीं आया। साल 2013 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अधिकारिक तौर पर पाकिस्तानी कलाकारों पर भारत में काम करने पर पाबंदी लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। फवाद खान की बात की जाए तो उन्होंने खूबसूरत, ऐ दिल है मुश्किल, कपूर एंड संस से लोगों का दिल जीता है। वह वाणी कपूर के साथ आरती एस बगड़ी की फिल्म अबीर गुलाल से वापसी करने के लिए तैयार हैं। ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म इसी साल 9 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान के बॉलीवुड में वापसी पर देओल ने रखी राय

बेहद जहरीला है ये ग्रह, यहां आठ महीने का होता है एक दिन

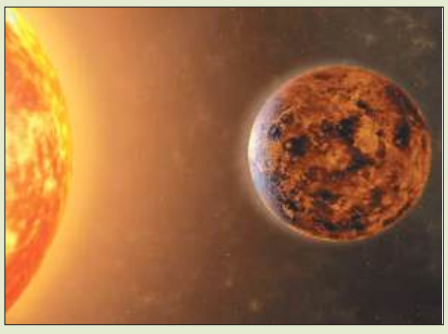

ब्रह्मांड के अंदर अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं, जिनके बारे में वैज्ञानिकों को भी कोई जानकारी नहीं है। आज हम आपको एक ग्रह के बारे में बताएंगे जिसे माना जाता है कि धरती का जुड़वा ग्रह है। यहां पर एक दिन धरती की तुलना में आठ महीनों का होता है। इस ग्रह का नाम है शुक्र यानी वीनस। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक, शुक्र सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह है और पृथ्वी का पड़ोसी है। कहा जाता है कि यह धरती का जुड़वा ग्रह है। आकार और घनत्व के मामले में यह धरती के बराबर है, लेकिन दोनों एक दूसरे मिलते हुए जुड़वा नहीं हैं। दोनों के बीच कुछ असमानताएं भी हैं। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि बुध ग्रह (मरक्युरी) सूर्य के अधिक नजदीक है, लेकिन शुक्र का तापमान उससे ज्यादा है। आपको जानकार हैरानी होगी कि शुक्र ग्रह का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस ग्रह पर हवा का दबाव धरती से 90 गुना अधिक है। यह उसी तरह है, जिस तरह आप समुद्र के काफी अंदर जाने पर महसूस करेंगे। हम सभी जानते हैं कि धरती पर एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन शुक्र अपनी धुरी पर बहुत धीमे घूमता है। इसकी वजह से धरती की तुलना में एक दिन 243 दिनों का होता है। धरती पर 243 दिन पूरे होते हैं, तो शुक्र पर एक दिन होगा, लेकिन धरती की तुलना में शुक्र ग्रह सूर्य का चक्कर अधिक तेजी से लगाता है। इसकी वजह से यहां पर 225 दिनों का ही एक साल होता है। वीनस की सतह सख्त है। सबसे हैरानी बात है कि इसका एक दिन 5,832 घंटों का होता है। इस ग्रह पर ज्वालामुखी हैं, पहाड़ हैं, खाई हैं और कई पठार भी मौजूद हैं। आपको जानकारी हैरानी होगी यह ग्रह जहरीला है। इस पर सल्फ्यूरिक एसिड का घना कोहरा छाया रहता है। इसकी वजह से यह सड़े हुए अंडे की तरह बदबू करता है।

अजब-गजब | इस शख्स ने प्लास्टिक की बोतलों से बनाया तैरता हुआ द्वीप

अब पर्यटकों की मेजबानी करके कमाता है पैसे

मेक्सिको में एक शख्स ने गजब का कारनामा किया है। उसने डेढ़ लाख प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल करके अपना खुद का द्वीप बनाया है। यह कारनामा करने वाले शख्स का नाम रिचर्ड सोवा है। वह पहले कारपेंटर का काम किया करते थे। उनके इस द्वीप पर एक घर भी है, जिसमें इंसानी जरूरत की सभी चीजें मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने द्वीप पर एक बगीचा भी लगाया है। रिचर्ड उनके द्वीप पर आने वाले पर्यटकों से पैसा कमाते हैं।

द सन की रिपोर्ट के अनुसार, एक बिल्डर के रूप में 13 सालों तक काम करने के बाद रिचर्ड सोवा ने इस इकोलॉजिकल द्वीप को बनाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने जिस मैटेरियल का इस्तेमाल किया उसे कुछ लोगों ने हैरान कर दिया। उन्होंने अपने तैरते हुए द्वीप को सहारा देने के लिए डेढ़ लाख प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल किया है। इन बोतलों को लोगों ने कूड़े-कचरे में फेंक दिया था।

उन्होंने कूलेस्ट थिंग को बताया, 'मैंने साढ़े 6 साल पहले मैक्सिको में इस द्वीप की शुरुआत की थी। इसे मैरिटाइम ऑफिसर्स के साथ एक इकोलॉजिक बॉट के रूप में रजिस्टर्ड भी कराया है।'तैरती हुई लड़की पट्टियों पर मैंग्रोव पेड़ लगाने के बाद, जड़ें नीचे की ओर बढ़ने लगीं और स्ट्रक्चर और भी मजबूत हो गया। इस द्वीप ने छोटी मछलियों जैसे समुद्री जीवों को भी आकर्षित किया है, जो इसको अपना घर कहते हैं। रिचर्ड अपने द्वीप पर हिबिस्कस फूल, अदरक, एगेव और भी बहुत कुछ उगाते हैं। उनका कहना है कि द्वीप धीरे-धीरे आत्मनिर्भर हो रहा है।

वह अपने अनूठे द्वीप पर आने वाले पर्यटकों की मेजबानी करके पैसा कमाते हैं। इसी पैसे से उनका खर्च चलता है। रिचर्ड ने द्वीप पर बने घर की छत पर सोलर पैनल लगाए हैं। जो रेफ्रिजरेटर और स्टोव जैसे उपकरणों को बिजली देते हैं। रिचर्ड ने बारिश के पानी से चलने वाली एक सिंक, एक कंपोस्ट टॉयलेट और एक शंख से चलने वाला शॉवर भी लगाया है।

अपने द्वीप पर उन्होंने कई अनोखे आविष्कार किए हैं, जो नेचुरल पॉवर से चलते हैं। जैसे सोलर कुकर, जिस पर वह खाना बनाते हैं। रिचर्ड के पास एक 'बोतल नाव' भी है, जो हजारों प्लास्टिक की बोतलों से बनी है, जो टूटने पर भी तैरती है।

यूपीए सरकार की कूटनीति की वजह से पकड़ा गया राणा : चिदंबरम

पूर्व गृहमंत्री बोले- प्रत्यर्पण का मोदी सरकार ले रही क्रेडिट

» 2014 में सरकार बदलने के बाद भी यूपीए सरकार की नीतियों पर चली कार्यवाही

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर बयान देते हुए कहा है कि मुझे खुशी है कि 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य आरोपियों में से एक राणा को भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया, लेकिन पूरी कहानी बताना जरूरी है, जबकि मोदी सरकार इस घटनाक्रम का श्रेय लेने के लिए होड़ में लगी है, सच्चाई उनके दावों से कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि यह प्रत्यर्पण डेढ़ दशक की कठिन, परिश्रमी और रणनीतिक कूटनीति का परिणाम है, जिसकी शुरुआत, अगुवाई और निरंतरता यूपीए सरकार ने अमेरिका के साथ समन्वय से सुनिश्चित की। पी चिदंबरम ने कहा कि इस दिशा में पहली बड़ी कार्रवाई 11 नवंबर 2009 को हुई, जब एनआईए ने नई दिल्ली में डेविड कोलमैन हेडली (अमेरिकी नागरिक), तहव्वुर राणा (कनाडाई नागरिक) और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया।

उसी महीने कनाडा के विदेश मंत्री ने भारत के साथ खुफिया सहयोग की पुष्टि की जो की यूपीए सरकार की कुशल विदेश नीति का सीधा परिणाम था। चिदंबरम ने कहा कि 2014 में सरकार बदलने के बाद भी, जो प्रक्रिया चल रही थी, वह यूपीए सरकार के समय शुरु हुई संस्थागत पहल की वजह से जीवित रही। 2015 में हेडली ने सरकारी गवाह बनने की पेशकश की। 2016 में मुंबई की अदालत ने उन्हें क्षमादान दिया, जिससे ज़बीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुदाल के खिलाफ केस मजबूत हुआ। दिसंबर 2018 में एनआईए की टीम प्रत्यर्पण से जुड़ी कानूनी बाधाएं सुलझाने अमेरिका गई और जनवरी 2019 में बताया गया कि राणा को अमेरिका में अपनी सजा पूरी करनी होगी। राणा की रिहाई की तारीख 2023 निर्धारित की गई, जिसमें पहले से की गई कैद की अवधि भी जोड़ी गई थी। यह मजबूत नेता की त्वरित कार्रवाई नहीं थी, बल्कि वर्षों की मेहनत से आगे बढ़ रही न्याय की प्रक्रिया थी। चिदंबरम ने कहा कि कानूनी अड़चनों के बावजूद, यूपीए सरकार ने संस्थागत कूटनीति और विधिक प्रक्रियाओं के माध्यम से लगातार प्रयास जारी रखा। 2011 के अंत से पहले, एनआईए की एक तीन सदस्यीय टीम अमेरिका गई और हेडली से पूछताछ की। परस्पर कानूनी सहायता संधि के तहत अमेरिका ने जांच के अहम सबूत भारत को सौंपे, जो दिसंबर 2011 में दायर एनआईए की चार्जशीट का हिस्सा बने।

'यूपीए सरकार ने प्रर्त्यण पर बनाए रखा दवाब'

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, एफबीआई ने 2009 में राणा को शिकागो से गिरफ्तार किया, जब वह कोपेनहेगन में एक नाकाम आतंकी हमले की साजिश में लश्कर-ए-तैयबा की मदद कर रहा था. हालांकि जून 2011 में अमेरिकी अदालत ने उन्हें 26/11 हमले में सीधे शामिल होने के आरोप से बरी कर दिया, लेकिन अन्य आतंकी साजिशों में दोषी पाकर उन्हें 14 साल की सजा सुनाई। यूपीए सरकार ने इस निर्णय पर सार्वजनिक रूप से निराशा जताई और कूट-नीतिक दबाव बनाए रखा।

राणा का प्रत्यर्पण नए भारत का संकल्प : पूनावाला

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह सभी सुरक्षा, आतंकवाद निरोधक, अभियोजन और खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ी जीत है। पूनावाला ने आगे कहा कि प्रत्यर्पण इस बात का संकल्प है कि भारत आतंकी हमलों पर चुप नहीं रहेगा बल्कि कड़ा जवाब देगा। उन्होंने कहा कि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण, न केवल 138 भारतीय पीड़ितों के लिए बल्कि कई अन्य देशों के पीड़ितों के लिए भी न्याय और समाधान सुनिश्चित करने और उसके करीब पहुंचने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। शहजाद पूनावाला ने दावा किया कि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण कोई आम प्रत्यर्पण नहीं है, ये नए भारत के संकल्प का प्रतिबिंब है। जिसे 2019 में पीएम नरेन्द्र मोदी जी ने परिभाषित करते हुए कहा था? कि अगर कोई भारत की अखंडता, एकता, सुरक्षा, अस्मिता या किसी भी निर्दोष भारतवासी पर हमला करने की जुर्रत करेगा, तो भारत ऐसे आतंकी को पाताल से भी खोज कर न्याय के पथ पर लाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि आज तहव्वुर राणा जब भारत लाया जा रहा, तो ये एक चेतावनी भी है। हर एक उस आतंकी के लिए, आतंकी साजिशकर्ता के लिए कि चाहे आप दुनिया के किसी कोने में छिप कर क्यों न बैठे हो, भारत आपको चुन चुन कर ढूंढेगा और न्याय के पथ पर लाएगा। भाजपा नेता ने कहा कि घरेलू आतंकवाद के कई मामलों में हमारी एजेंसियों ने अपराधियों को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है।

धोनी आज लेंगे केकेआर की क्लास

» गायकवाड़ के चोटिल होने के बाद बने चेन्नई के कप्तान

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सीएसके को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ मुकाबले से पहले तगड़ा झटका लगा है। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चोट के कारण बाहर हो गए हैं। उनकी जगह महेंद्र सिंह धोनी को टीम की कप्तानी सौंपी गई है। वह अब गायकवाड़ की जगह आगामी मैचों में टीम का नेतृत्व करते नजर आएंगे। चेन्नई आज कोलकाता के खिलाफ मैच खेलेगी। गायकवाड़ कोहनी की चोट की पुष्टि टीम के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने की। उन्होंने बताया कि स्टार बल्लेबाज की जगह धोनी अब टीम का नेतृत्व करते नजर आएंगे।

चेन्नई सुपर किंग्स ने बीच सत्र में कप्तान बदलकर सभी को चौंका दिया है। हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सीएसके ने टीम की कमान किसी अन्य को सौंपी है। इससे पहले टीम ने आईपीएल 2024 की शुरुआत से ठीक पहले ऋतुराज को कप्तान बनाया था। धोनी और गायकवाड़ के अलावा सुरेश रैना और रवींद्र जडेजा टीम की कमान संभाल चुके हैं। रैना धोनी की गैरमौजूदगी में कमान संभाल रहे थे, जबकि जडेजा को आईपीएल 2022 में टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले पूरी तरह से नया कप्तान बनाया गया था। मौजूदा सत्र में पांच बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। अबतक खेले पांच मैचों में उन्हें चार बार मुंह की खानी पड़ी है।

उन्होंने सिर्फ सत्र के शुरुआती मुकाबले में मुंबई को मात दी थी। फिलहाल टीम दो अंक और -0.889 के नेट रन रेट के साथ अंक तालिका में नौवें पायदान पर है।

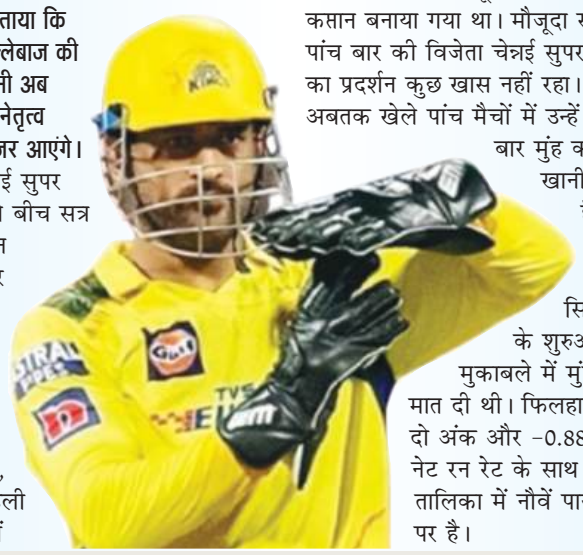

धोनी ने सीएसके को 133 मैच में दिलाई है जीत

धोनी ने 226 मैचों में कप्तानी की और 133 में सीएसके को जीत दिलाई। वह कप्तानी करते हुए 100 से ज्यादा आईपीएल मैच जीतने वाले इकलौते कप्तान हैं। उनके बाद रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 158 मुकाबलों में टीम का नेतृत्व किया है और 87 में जीत दिलाई है।

केएल राहुल ने छीना आरसीबी से मैच

बंगलुरू। केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स की 100 से ज्यादा रनों की नाबाद साझेदारी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को उनके घर में छह विकेट से पटखनी दे दी। इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने 20 ओवर में सात विकेट खोकर 163 रन बनाए। जवाब में दिल्ली ने 17.5 ओवर में चार विकेट खोकर 169 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। अक्षर पटेल के नेतृत्व वाली टीम की यह लगातार चौथी जीत है जबकि आरसीबी को पांच मैचों में दूसरी बार मुंह की खानी पड़ी है। केएल ने 37 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 93 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके बल्ले से सात चौके और छह छक्के निकले। वहीं, स्टब्स ने चार चौके और एक छक्के की सहायता से 38* रन बनाए।

'आशाओं को केंद्र से नहीं मिल रही मदद'

» विरोध प्रदर्शन के बीच सीएम विजयन ने कहा- आशा कार्यकर्ताओं को सरकार का पूरा समर्थन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोच्चि। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) राज्य सरकार की मंशा से अवगत हैं कि वे उनका पूरा समर्थन करेंगे। उन्होंने सचिवालय के बाहर चल रहे विरोध प्रदर्शन में कम संख्या में लोगों के शामिल होने को इसका सबूत बताया। प्रदर्शनकारियों की कम संख्या के बावजूद, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को खारिज नहीं किया है और प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं के साथ छह दौर की चर्चा की है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी कार्य स्थितियों में सुधार के लिए पहले भी कई कदम उठाए जा चुके हैं।

हालांकि, आशा कार्यकर्ताओं ने 21,000 रुपये मानदेय और 5 लाख रुपये के सेवानिवृत्ति लाभ की अपनी मांगें पूरी होने तक अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने की कसम खाई है। विजयन ने स्पष्ट किया कि सरकार कर्मचारियों की असहमति के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर प्रशासन मानदेय बढ़ाने को तैयार है। 99 प्रतिशत आशा कार्यकर्ताओं को पता है कि सरकार का उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। उन्हें लगता है कि हम उनकी मदद करने के लिए हैं और इसीलिए वे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बजाय अपना कर्तव्य निभाना जारी रखती हैं।

टी वीना के खिलाफ ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच, राजनीति से प्रेरित

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपनी बेटी टी वीना के खिलाफ चल रही गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) में कथित तौर पर 1.7 करोड़ रुपये के अवैध भुगतान के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। विजयन ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई उन्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने के उद्देश्य से की गई थी। कांग्रेस और भाजपा की मांगों के जवाब में उन्होंने कहा कि आप मेरे इस्तीफे की उम्मीद कर सकते हैं। एसएफआईओ कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड द्वारा वीना की अब बंद हो चुकी आईटी फर्म एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को कथित तौर पर ऐसी सेवाओं के लिए किए गए भुगतान से जुड़े मामले की जांच कर रहा है, जो कभी प्रदान ही नहीं की गईं। रिपोर्टों से पता चला है कि ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने की तैयारी कर रहा है। वित्तीय धोखाधड़ी में अपनी बेटी की कथित संलिप्तता पर, विजयन ने कहा कि बिनेश कोडियेरी के मामले में, कोडियेरी बालाकृष्णन का नाम नहीं लिया गया था। इस मामले में, मेरा नाम लिया गया है। पार्टी ने मामले के पीछे की मंशा को स्पष्ट रूप से पहचान लिया है। मामला अदालत में है। इसे अपने तरीके से चलने दें।

गुंडों और गैंगस्टरों के खेल का मैदान बन गया है पंजाब : जयवीर

» भगवंत सरकार पर हमलावर हुई भाजपा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। जालंधर में भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के घर के बाहर रात करीब 1 बजे धमाका हुआ। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और विस्फोट की प्रकृति का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। हालांकि, इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है।

पंजाब में कानून व्यवस्था और कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से खोखली हो चुकी है और मान केजरीवाल के फुलटाइम ओएसडी की तरह काम कर रहे हैं। उन्हें पंजाब की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। जयवीर ने कहा कि आज पंजाब तरक्की का केंद्र नहीं बल्कि गुंडों और गैंगस्टरों का खेल का मैदान बन गया है। अगर मान में थोड़ी भी शर्म बची है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।

अनिल जयहिंद बने कांग्रेस ओबीसी विभाग के नए अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खरगे ने किया नियुक्त

» बिहार के रहने वाले हैं जयहिंद

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस ने अपने ओबीसी विभाग के नए प्रमुख के रूप में अनिल जयहिंद (अनिल कुमार यादव) को नियुक्त किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ओबीसी विभाग के नए अध्यक्ष के रूप में अनिल जयहिंद की नियुक्ति की है।

कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से इस नियुक्ति की जानकारी दी गई है। अनिल जयहिंद ने हरियाणा के पूर्व मंत्री अजय सिंह यादव की जगह ली है जो कि इससे पहले कांग्रेस के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष थे। कांग्रेस पार्टी ने इसके साथ ही मीडिया पैनलिस्ट आलोक शर्मा को राष्ट्रीय सचिव और पंजाब के सह प्रभारी के पद से मुक्त कर दिया है। आलोक शर्मा मीडिया पैनलिस्ट की भूमिका निभाते रहेंगे।

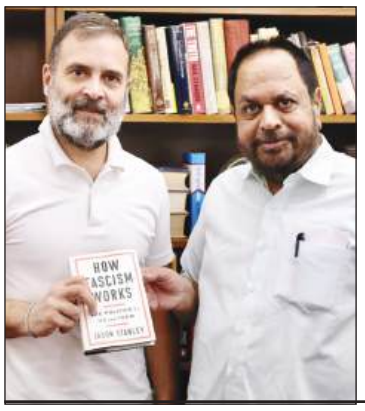

सामाजिक कार्यकर्ता हैं अनिल जयहिंद

अनिल जयहिंद मूलत: बिहार के रहने वाले हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अनिल जयहिंद की सोशल मीडिया प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने बी पी मंडल और शरद यादव के साथ भी काम किया है। अनिल जयहिंद ने बताया है कि उनके पिता पिता ब्रह्म में थे और नेताजी सुभाष बोस के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़े थे।

वक्फ एक्ट के खिलाफ श्रीनगर में पीडीपी का विरोध प्रदर्शन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

श्रीनगर। पार्टी महासचिव खुर्शीद आलम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पीडीपी कार्यकर्ता अधिनियम के विरोध में एकत्र हुए थे, जिसे पिछले सप्ताह संसद में पारित किया गया था। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने शहर के केंद्र की ओर मार्च करने का प्रयास किया, कार्यालय के बाहर तैनात पुलिस ने उन्हें रोक दिया और गेट बंद कर दिए, जिससे प्रदर्शन परिसर तक ही सीमित हो गया।

पुलिस ने शुक्रवार को हाल ही में पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) द्वारा निकाले जा रहे विरोध मार्च को विफल कर दिया। इसके लिए पार्टी मुख्यालय पर शेर-ए-कश्मीर पार्क के पास बैरिकेडिंग कर दी गई और प्रदर्शनकारियों को परिसर के अंदर ही रोक दिया गया। पार्टी महासचिव खुर्शीद आलम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पीडीपी कार्यकर्ता अधिनियम के विरोध में एकत्र हुए थे, जिसे पिछले सप्ताह संसद में पारित किया गया था। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने शहर के केंद्र की ओर मार्च करने का प्रयास किया, कार्यालय के बाहर तैनात पुलिस ने उन्हें रोक दिया और गेट बंद कर दिए, जिससे प्रदर्शन परिसर तक ही सीमित हो गया।

महंगाई भौजाई लगती है, तो भाजपा को वोट दीजिए : तेजस्वी

» राजद नेता के बयान पर मचा सियासी घमासान

» जदयू ने भाजपा नेता चौबे के बयान से किया किनारा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। बिहार में कुछ ही महीनों में विधान सभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर अभी से ही बयानबाजी और जुबानी हमले होने लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज कुछ ऐसा बोला जो आज चर्चा का विषय बन गया है। वहीं पीके व जदयू व भाजपा ने भी सियासी राग शुरू कर दिया है। जहां भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को उपप्रधानमंत्री बनाने की बात कहकर सियासी माहौल गर्मा दिया है हालांकि जदयू ने किनारा कर लिया।

वहीं तेजस्वी यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर महंगाई भौजाई लगती है, तो भाजपा को वोट दीजिए। तेजस्वी यादव ने आज गोपालगंज में भाजपा और नीतीश कुमार दोनों पर जमकर जुबानी हमला किया। उन्होंने जनता से कहा कि अगर महंगाई चाहिए तो भाजपा को वोट दीजिए। अगर बेरोजगारी चाहिए तो भाजपा को वोट दीजिए। अगर पलायन चाहिए तो भाजपा को वोट दीजिए। अगर गरीबी चाहिए तो भाजपा को वोट दीजिए। तेजस्वी यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही जनता को भूल जाते हैं।

मैं नीतीश या तेजस्वी का चैलेंजर नहीं : पीके

जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने कहा कि पार्टी विद अ डिफरेंस का मतलब यह नहीं कि हम जनता से संपर्क ही न करें। अंतर संवाद के कंटेंट में है। हमने दो साल तक पैदल यात्रा की और आज भी गांव-गांव जा रहे हैं। अगर राज्य भर के लोग एक जगह मिलना चाहते हैं, तो क्या यह गलत है? हम ताकत नहीं दिखा रहे। अगस्त-सितंबर में ताकत दिखेगी। यह रैली जन सुराज परिवार की भावना को पूरा करने के लिए है। उन्होंने कहा मैं नीतीश या तेजस्वी का चैलेंजर नहीं हूं, मैं उस व्यवस्था का चैलेंजर हूं, जिसने 35 साल से बिहार को राजनीतिक बंधुआ मजदूर बना रखा है। लोग लालू के डर से नीतीश-बीजेपी को, और नीतीश-बीजेपी के डर से लालू को वोट देते हैं। जन सुराज इस बंधन को तोड़ेगी। अगर पार्टी तय करती है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं राघोपुर से भी लड़ सकता हूं।

नीतीश कुमार से जनता को उम्मीद : नीरजकुमार

जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने अश्विनी चौबे के बयान से किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि कौन क्या बोलता है, यह उनका विषय नहीं है। नीरज कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह के भाषण का जिक्र किया जो उन्होंने पटना में दिया था। उनके मुताबिक अमित शाह ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार का नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राजनीतिक जोड़ी से विपक्ष राजनीतिक रूप से लकवा ग्रस्त घोषित हो गया है। नीरज कुमार के मुताबिक एनडीए ने 30 सीटों पर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। उन्होंने कहा कि 174 से ज्यादा सीटों पर हमारी बढ़त है। नीतीश कुमार से जनता को उम्मीद है। जनता उन्हें उम्मीद भरी निगाहों से देखते है।

पूर्व न्यायाधीश काटजू के बयान से टीएमसी नाराज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू अक्सर अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्टों को लेकर विवादों में घिर जाते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उनकी हालिया टिप्पणी को लेकर भी बड़ा विवाद हो गया है जिसके चलते उन्हें अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट करना पड़ा।

हम आपको बता दें कि पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने सोशल मीडिया पर की गयी एक पोस्ट में बंगालियों से ममता बनर्जी के लिए एक अच्छा पति खोजने के लिए कहा था। इस पोस्ट को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने काफी सख्त प्रतिक्रिया दी। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, वह एक थप्पड़ के हकदार हैं। इसके बाद मार्कंडेय काटजू ने फिर से पोस्ट किया और कहा, भारत में मजाक करना खतरनाक है। हम आपको बता दें कि अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए मशहूर मार्कंडेय काटजू ने ममता बनर्जी पर कटाक्ष करने के लिए कोई खास कारण नहीं बताया। वह पहले भी ममता बनर्जी की आलोचना और उनकी प्रशंसा कर चुके हैं।उधर, सोशल मीडिया पर लोग मार्कंडेय काटजू की टिप्पणी की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि काटजू अब अपनी विवादित पोस्ट को डिलीट कर चुके हैं। मगर तृणमूल कांग्रेस समर्थक उनको घेर रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने एक्स पर लिखा- अगर यह सच में इस व्यक्ति ने कहा है और अगर वह माफी नहीं मांगता और इसे डिलीट नहीं करता, तो चाहे वह किसी भी पद पर हो, अगर मुझे खबर मिलती है कि उसने बंगाल में कदम रखा है, तो मैं आगे बढ़कर उसे थप्पड़ मारूंगा।

यूपी व बिहार के कई जिलों में वज्रपात, 70 लोगों की मौत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। देश के कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि की चपेट में आने से सौ से ज्यादा की मौत लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सबसे ज्यादा बिहार व यूपी में नुकसान हुआ है। बिहार में 25 व यूपी में 23 लोगों की मौत हो गई। अन्य राज्यों में अलग-अलग जगहों से लगभग 50 लोगों के मरने की खबरें। इस वर्षा से किसानों को भी बहुत नुकसान हुआ है।

यूपी के सीएम योगी ने मृतकों को चार-चार लाख की सहायता देने की घोषणा की है जबकि बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी बयान के अनुसार, नालंदा में 18 लोगों की मौत हुई। इसके बाद सीवान में दो, कटिहार, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर और जहानाबाद में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई। बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन घटनाओं में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। बुधवार को बिहार के चार जिलों में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 13 लोगों की मौत हो गई थी।

यूपी में 55 जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का भी अलर्ट

उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को भी कई जिलों में भयंकर आंधी और तूफान आने की संभावना है। इस दौरान बादल गरजेंगे। बारिश की संभावना भी बनी हुई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। इस समय खेलों में फसल पकी हुई है। बारिश और ओलो के कारण फसल को नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद अब लोगों को थाड़ी राहत मिली है और मौसम पूरी तरह बदल गया है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। कई जगहों पर आंधी तूफान और बारिश आने की संभावना है। इस दौरान ठंडक भी महसूस हुई है। राजधानी लखनऊ में भी काले बाद छाए और बारिश भी हुई। मौसम विभाग की मानें तो राज्य में शुक्रवार को भी आंधी तूफान, बादल गरजने, बिजली की चमक के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। शनिवार को भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है। सोमवार से मौसम फिर गर्मी भरा हो सकता है।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित एवं 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। महाराष्ट्र कार्यालय :- 2 जी, कृष्णा कुटीर सागरिका CHS जुहू तारा रोड जुहू- मुंबई- 400049। संपादक - संजय शर्मा, विधि सलाहकार : सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, वित्तीय सलाहकार : संदीप बंसल, कार्टूनिस्ट : हसन जैदी, दूरभाष : 0522- 4078371 | Email : daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in | RNI-UPHIN/2015/62233 डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।